भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समानता और नीति प्रभाव का अध्ययन

मनोरमा विश्वकर्मा[1] डॉ. निधि अवस्थी[2]

[1]पी.एच.डी. शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, थनरा, करैरा, शिवपुरी (म.प्र.)
[2]शोध निर्देशक, गृह विज्ञान विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, थनरा, करैरा, शिवपुरी (म.प्र.)

सारांश

यह अध्ययन “भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समानता और नीति प्रभाव का अध्ययन” भारत की शिक्षा प्रणाली में समान अवसरों और नीति क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, विद्यालय का प्रकार, और शिक्षक गुणवत्ता जैसी स्थितियाँ शैक्षिक समानता को कैसे प्रभावित करती हैं। इस शोध में मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें 384 उत्तरदाताओं (शिक्षक, अभिभावक और प्रशासक) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण SPSS सॉफ़्टवेयर द्वारा किया गया। सांख्यिकीय परीक्षणों जैसे वन-सैंपल स्टैटिस्टिक्स, एएनओवा और कोएफिशिएंट्स का उपयोग करके विद्यालय का प्रकार (β=.257), शिक्षक गुणवत्ता (β=.208), और आर्थिक पृष्ठभूमि (β=.100) जैसे कारकों के महत्वपूर्ण प्रभाव पाए गए। परिणामों से यह निष्कर्ष निकला कि NEP 2020 ने शिक्षा में समानता, समावेशिता और गुणवत्ता सुधार की दिशा में सकारात्मक योगदान दिया है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन सीमित है। अध्ययन यह सुझाव देता है कि शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना और स्थानीय भागीदारी को मजबूत करके नीति के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य शब्द: प्राथमिक शिक्षा, समानता, सामाजिक-आर्थिक कारक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), शिक्षक गुणवत्ता, शैक्षिक सुधार, डिजिटल पहुँच, नीति क्रियान्वयन

1. परिचय

भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली वर्तमान में नीति सुधार और स्थायी असमानता के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। शिक्षा की पहुँच बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने के अनेक प्रयासों के बावजूद, जाति, आय, क्षेत्र और लिंग पर आधारित गहरी असमानताएँ अब भी शैक्षिक समानता के लक्ष्य को चुनौती देती हैं। ये असमानताएँ केवल संस्थागत नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ी हुई हैं, जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति और उससे होने वाले लाभ को गहराई से प्रभावित करती हैं। विद्वान घोष (2024) के अनुसार, सामाजिक-आर्थिक कारक जैसे गरीबी और सामाजिक वर्ग विभाजन प्राथमिक शिक्षा के परिणामों

को गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे समाज की पारंपरिक असमानताएँ बनी रहती हैं। इसके प्रत्युत्तर में, भारतीय शिक्षा नीतियाँ, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। फिर भी, डिजिटल विभाजन, वित्तीय कमी और अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण जैसी चुनौतियाँ, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी परिस्थितियों में, असमानता को और गहरा करती हैं (सिंह आदि, 2023)। यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि शैक्षिक नीतियों ने भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समानता को कितना प्रभावित किया है और क्या ये नीतियाँ वास्तव में प्रणालीगत खाई को पाट रही हैं या सुधार के नाम पर नई असमानताएँ उत्पन्न कर रही हैं।

1.1. सामाजिक-आर्थिक कारक और शैक्षिक पहुँच पर प्रभाव

सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ भारत में प्राथमिक शिक्षा तक समान पहुँच के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं। निम्न-आय वाले परिवारों के बच्चों को अपर्याप्त स्कूल ढाँचे, परिवहन की कमी और पारिवारिक आय में योगदान की आवश्यकता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में यह स्थिति और गंभीर होती है, जहाँ संसाधनों की कमी और शिक्षक की अनुपलब्धता बच्चों की शिक्षा में बाधा बनती है (चंद, 1994)। शिक्षा नीतियाँ पहुँच सुधारने के लिए बनाई गई हैं, परंतु जाति आधारित असमानताओं को दूर करने में अक्सर असफल रहती हैं, जो शैक्षिक परिणामों पर गहरा प्रभाव डालती हैं (मांजरेकर, 2005)।

लिंग आधारित असमानताएँ इन चुनौतियों को और बढ़ाती हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों की लड़कियाँ प्रारंभिक विवाह, घरेलू ज़िम्मेदारियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण स्कूल से बाहर हो जाती हैं। यद्यपि राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रोत्साहनों ने इन खाइयों को पाटने का प्रयास किया है, लेकिन इनका क्रियान्वयन असमान और स्थानीय स्तर पर सीमित रहा है (कुरियाकोस और अय्यर, 2016)। इसके अलावा, समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियाँ, जैसे NEP 2020, संसाधन वितरण और स्थानीय शासन की सीमाओं के कारण प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पातीं (सय्यद आदि, 2013)।

1.2. भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति

भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा की पहुँच बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम और सर्व शिक्षा अभियान जैसी नीतियों ने नामांकन में वृद्धि और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। फिर भी, सीखने के परिणाम, शिक्षक गुणवत्ता, अवसंरचना और क्षेत्रीय असमानताओं जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। अध्ययन बताते हैं कि कागज़ों पर तो प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक प्रतीत होती है, लेकिन कई विद्यालयों में कार्यशील शौचालय, पुस्तकालय और प्रशिक्षित शिक्षक अब भी नहीं हैं (पंडित, 2016)। राज्यों के भीतर भी जिलों के प्रदर्शन में बड़े अंतर पाए जाते हैं, जो नीति क्रियान्वयन में असमानता को दर्शाते हैं (कायल, 2019)।

शहरी झुग्गी क्षेत्रों के बच्चों को भी विशिष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, गुवाहाटी में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि झुग्गियों में रहने वाले बच्चे आर्थिक कठिनाइयों, संसाधनों की कमी और पारिवारिक सहयोग की अनुपस्थिति के कारण स्कूलों में नियमित उपस्थिति नहीं

दे पाते और उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है (गोसवामी और रॉयचौधरी, 2017)। यद्यपि नीति ढाँचे तैयार हैं, परंतु वास्तविक समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ज़मीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नीतिगत सुधार आवश्यक हैं।

1.3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और उसका प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक परिवर्तन का संकेत देती है, जो समग्र, लचीली और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। प्राथमिक स्तर पर, यह नीति 5+3+3+4 संरचना को लागू करती है, जिसमें प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, और बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य रटने वाली शिक्षा प्रणाली से हटकर समझ-आधारित सीखने को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में शिक्षा और समुदाय की भागीदारी पर जोर देने से शिक्षा की पहुँच और सहभागिता बढ़ाने की संभावना है। हालांकि, शिक्षक की कमी, अवसंरचना की अपर्याप्तता और डिजिटल विभाजन जैसी समस्याएँ इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बन रही हैं (शुभम, 2024)।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ भी सुधारों की पहुँच को सीमित कर सकती हैं, जब तक राज्य स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी विकास और स्थानीय प्रशासन में पर्याप्त निवेश नहीं किया जाता (सिंह और नारायणन, 2023)। समग्र रूप से, NEP 2020 एक दूरदर्शी ढांचा प्रस्तुत करती है, लेकिन इसके पूर्ण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सशक्त और सतत क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

1.4. चुनौतियाँ, निष्कर्ष और नीतिगत सुझाव

नीति सुधारों जैसे NEP 2020 के बावजूद, भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली अब भी कई गंभीर क्रियान्वयन चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें अपर्याप्त अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, और व्यापक क्षेत्रीय असमानताएँ शामिल हैं। एक प्रमुख चुनौती डिजिटल विभाजन है, जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा और आधुनिक शिक्षण विधियों से वंचित करता है (दास, 2023)। इसके अलावा, विद्यालयों के पाठ्यक्रम को NEP के बहु-विषयक और कौशल-आधारित लक्ष्यों के अनुरूप ढालना कठिन साबित हो रहा है, क्योंकि वर्तमान प्रणाली कठोर संरचनाओं और राज्य स्तरीय क्षमता की कमी से ग्रस्त है (बड़े और चव्हाण, 2023)।

फिर भी, हालिया अध्ययनों में सुधार के कई मार्ग सुझाए गए हैं। शिक्षकों की शिक्षा और सतत प्रशिक्षण को मजबूत करना कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य है। नीतियों को शहरी और ग्रामीण खाई को पाटने के लिए संसाधनों के समान वितरण और डिजिटल पहुँच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है ताकि पारदर्शिता और डेटा-आधारित निर्णय सुनिश्चित किए जा सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतिगत क्रियान्वयन में स्थानीय सरकारों और सामुदायिक हितधारकों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए, जिससे NEP सुधार विविध क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी रूप से लागू हो सकें (मुरारी, 2024)। इन उपायों से नीति की

दृष्टि को वास्तविक परिणामों में बदला जा सकता है और भारत के प्राथमिक शिक्षार्थियों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

2. समस्या विवरण

भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में आज भी समानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, सरकारी और निजी विद्यालयों, तथा सामाजिक-आर्थिक वर्गों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों की उपलब्धता में स्पष्ट असमानताएँ हैं। कई बच्चे अभी भी बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण तक नहीं पहुँच पाते। हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने समान अवसर और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इसकी जमीनी प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से परखी नहीं गई है। यह अध्ययन इसी अंतर को समझने और नीति के प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

3. अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समानता और नीति प्रभाव की वास्तविक स्थिति को उजागर करने में सहायक होगा। इसके निष्कर्ष शिक्षा नीति निर्माताओं, शिक्षकों और प्रशासकों को यह समझने में मदद करेंगे कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अध्ययन यह भी दर्शाएगा कि NEP 2020 के बाद शिक्षा में समान अवसरों की दिशा में क्या बदलाव आए हैं और किन सामाजिक-आर्थिक कारकों से यह प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस शोध के माध्यम से भारत में गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्राप्त होंगे।

4. उद्देश्य

1. भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक समानता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभाव का आकलन करना।

5. साहित्य समीक्षा

घोष (2024) का मानना है कि सामाजिक-आर्थिक कारक अब भी भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समानता प्राप्त करने में बड़ी बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं। उनके संरचनात्मक मॉडल से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी, जातिगत भेदभाव और भौगोलिक अलगाव जैसे तत्व वंचित समुदायों के बच्चों की शिक्षा तक पहुँच और सीखने के परिणामों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। कायल (2019) ने भी इस निष्कर्ष का समर्थन करते हुए बताया कि जिलावार शैक्षिक प्रदर्शन में भारी असमानताएँ पाई जाती हैं, जो अक्सर असमान सार्वजनिक निवेश और प्रशासनिक अक्षमताओं से जुड़ी होती हैं। वहीं गोसवामी (2017) ने शहरी झुग्गियों में रहने वाले बच्चों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं – जैसे भीड़भाड़ वाली कक्षाएँ, बुनियादी अवसंरचना की कमी और सामाजिक कलंक – को रेखांकित किया है, जो उच्च विद्यालय त्याग दर का कारण बनते हैं। पंडित (2016) का कहना है कि यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी नीतियों ने

नामांकन दरों में सुधार किया है, लेकिन ये नीतियाँ शिक्षा में गहराई से जमी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने में असफल रही हैं। समग्र रूप से, ये सभी अध्ययन दर्शाते हैं कि नीति-स्तरीय प्रयासों के बावजूद गहरे संरचनात्मक अवरोध बने हुए हैं, जिन्हें केवल स्थानीय और समानता-केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है ताकि भारत में प्राथमिक शिक्षा की पहुँच का वास्तविक लोकतंत्रीकरण संभव हो सके।

सिंह (2023) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के परिवर्तनकारी लक्ष्यों की समीक्षा की है, जिसमें विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता, लचीले पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया गया है। हालांकि, वे चेतावनी देते हैं कि ग्रामीण और निम्न-आय वाले क्षेत्रों में गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मुरारी (2024) ने NEP 2020 को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG-4) से जोड़ते हुए परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि समानता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जा सकें। दास (2023) ने शिक्षक शिक्षा की मौजूदा स्थिति की आलोचना करते हुए पाया कि कई प्रशिक्षण संस्थानों में नीति द्वारा प्रस्तावित शिक्षण परिवर्तन के लिए आवश्यक क्षमता का अभाव है। इसी प्रकार, बड़े (2023) ने नौकरशाही जड़ता और अवसंरचनात्मक सीमाओं को नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए गंभीर खतरा बताया है, विशेषकर सरकारी विद्यालयों में। समग्र रूप से, ये सभी अध्ययन संकेत करते हैं कि यद्यपि NEP 2020 अपने डिज़ाइन में महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसकी सफलता जमीनी स्तर की तैयारी, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और शासन प्रणाली की दक्षता पर निर्भर करती है।

मांजरेकर (2005) ने शिक्षा तक पहुँच में लिंग आधारित असमानताओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि पितृसत्तात्मक मान्यताएँ, प्रारंभिक विवाह और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ अब भी ग्रामीण और पारंपरिक क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में बड़ी बाधा बनी हुई हैं। सय्यद (2013) ने शिक्षा सुधारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल ढाँचागत सुधारों तक सीमित रहते हैं और उन सांस्कृतिक एवं प्रणालीगत असमानताओं को नहीं छूते जो बहिष्करण को बनाए रखती हैं। कुरियाकोस (2016) का तर्क है कि शिक्षा सुधार केवल अवसंरचना और नामांकन संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्कृष्टता और समानता पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। चंद (1994) का अध्ययन, यद्यपि पुराना है, आज भी प्रासंगिक है क्योंकि उन्होंने बताया कि पूर्व सुधारों ने संस्थागत परिवर्तन के अवसरों का पूर्ण उपयोग नहीं किया, जिससे अनेक असमानताएँ बनी रहीं। इन सभी विद्वानों का सामूहिक मत है कि नीति पहलें तभी प्रभावी हो सकती हैं जब उनके साथ सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन भी हो। सामाजिक पदानुक्रमों को तोड़ना, समुदायों को सशक्त बनाना और शिक्षा के प्रति समाज के मूल्यों को पुनर्गठित करना भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में स्थायी, समावेशी और समान परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

6. अनुसंधान कार्यप्रणाली

इस अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण को मिलाकर एक मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण अपनाया गया। इसका उद्देश्य भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक समानता और नीतिगत प्रभाव का विश्लेषण करना था। 384 उत्तरदाताओं से प्राप्त मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण SPSS सॉफ़्टवेयर से किया गया, जबकि गुणात्मक जानकारी शिक्षकों और अभिभावकों के साक्षात्कार से प्राप्त हुई। इस संयोजन ने अध्ययन को व्यावहारिक, विश्वसनीय और नीति-उन्मुख निष्कर्ष प्रदान किए जो शैक्षिक समानता और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

6.1. औचित्य

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक समानता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अध्ययन का फोकस पहुंच, गुणवत्ता और नीति क्रियान्वयन में बनी असमानताओं की पहचान पर है, ताकि देशभर में समावेशी और समान प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए प्रमाण-आधारित सुझाव दिए जा सकें।

6.2. अनुसंधान रूपरेखा

इस अध्ययन में मिश्रित अनुसंधान रूपरेखा अपनाई गई है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। यह शैक्षिक समानता और एनईपी से संबंधित परिणामों को प्रभावित करने वाले सांख्यिकीय संबंधों और सामाजिक धारणाओं को समझने पर बल देती है। यह रूपरेखा सुनिश्चित करती है कि अध्ययन के निष्कर्ष न केवल विश्लेषण के लिए विश्वसनीय हों, बल्कि नीति-निर्माताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हों।

6.3. प्रश्नावली निर्माण

प्रश्नावली को पाँच भागों में विभाजित किया गया था – सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, संस्थागत और नीतिगत पहलू। इसमें उत्तरदाताओं की राय को मापने के लिए पाँच-बिंदु लिकर्ट स्केल का उपयोग किया गया। मात्रात्मक विश्लेषण में वन-सैंपल स्टैटिस्टिक्स, एनोवा, और कोएफिशिएंट्स परीक्षण शामिल थे, जिनका उपयोग प्रमुख चर के बीच संबंधों और नीति के शैक्षिक समानता पर प्रभाव की सांख्यिकीय महत्वपूर्णता मापने के लिए किया गया। प्रश्नावली द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेज़ी) थी ताकि यह अधिक लोगों के लिए सुलभ हो सके।

6.4. डेटा संग्रहण

डेटा संग्रह दो चरणों में किया गया – प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक डेटा 384 उत्तरदाताओं (शिक्षक, अभिभावक, और प्रशासक) से संरचित ऑनलाइन प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किया गया। द्वितीयक डेटा एनईपी 2020 दस्तावेज़ों, सरकारी शिक्षा रिपोर्टों, और शोध पत्रिकाओं से लिया गया। दोनों प्रकार के आंकड़ों के संयोजन से अध्ययन की सटीकता, गहराई और नीतिगत प्रासंगिकता सुनिश्चित की गई।

7. परिणाम

टेबल 1: डेमोग्राफी

	आवृत्ति	प्रतिशत		आवृत्ति	प्रतिशत
आपका लिंग क्या है?			आपका निवास क्षेत्र कौन-सा है?		
पुरुष	222	57.8	ग्रामीण क्षेत्र	108	28.1
महिला	162	42.2	शहरी क्षेत्र	150	39.1
आपका व्यवसाय क्या है?			अर्ध-शहरी क्षेत्र	126	32.8
नौकरी	134	34.9	आपकी स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या था?		
व्यवसाय	84	21.9	अंग्रेज़ी माध्यम	205	53.4
शिक्षक	67	17.4	हिंदी माध्यम	179	46.6
अन्य	99	25.8			

टेबल 1 से स्पष्ट है कि सर्वे में कुल 222 पुरुष (57.8%) और 162 महिलाएँ (42.2%) शामिल थीं। अधिकांश उत्तरदाता शहरी क्षेत्र (39.1%) से थे, जबकि ग्रामीण (28.1%) और अर्ध-शहरी (32.8%) क्षेत्र से भी संतुलित भागीदारी रही। व्यवसाय के अनुसार 34.9% नौकरीपेशा, 21.9% व्यवसायी, 17.4% शिक्षक और 25.8% अन्य श्रेणी में थे। शिक्षा के माध्यम में अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़े हुए प्रतिभागियों की संख्या 205 (53.4%) रही, जबकि हिंदी माध्यम के 179 (46.6%) प्रतिभागी थे। यह आँकड़े दिखाते हैं कि अध्ययन में विविध सामाजिक, भौगोलिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे, जो विश्लेषण को अधिक संतुलित बनाते हैं।

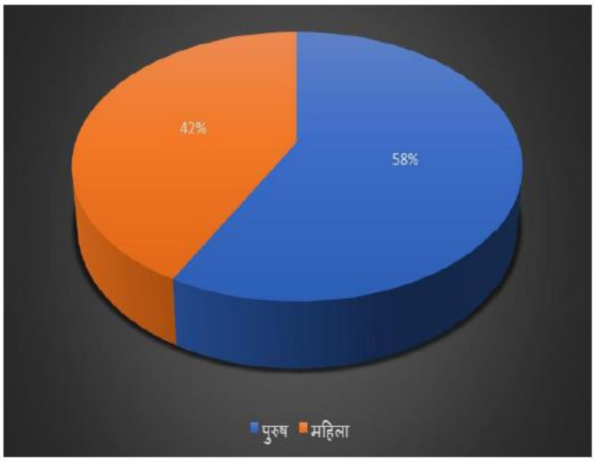

आपका लिंग क्या है?

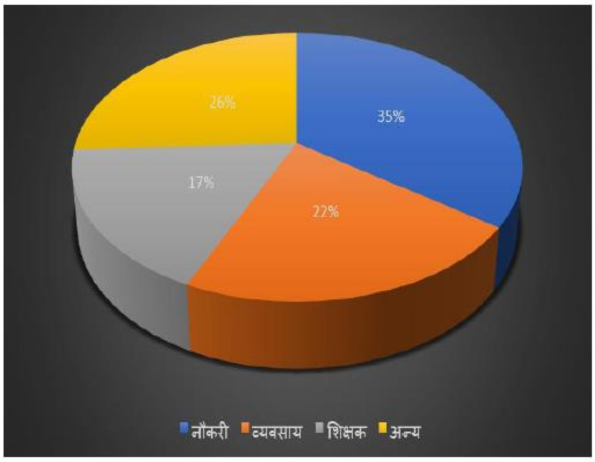

आपका व्यवसाय क्या है?

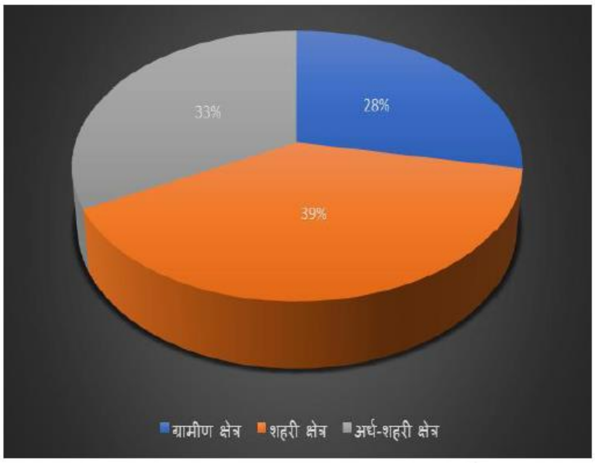

आपका निवास क्षेत्र कौन-सा है?

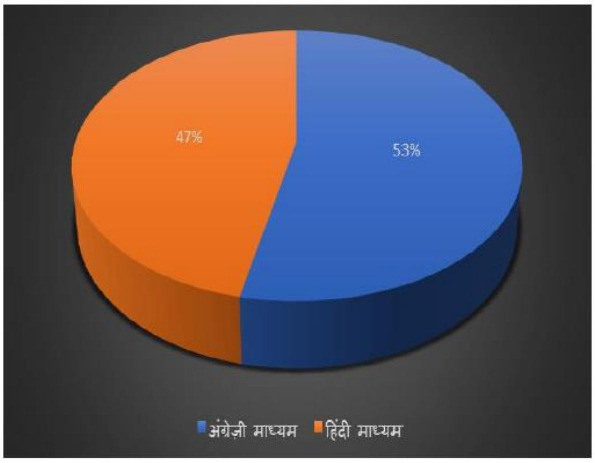

आपकी स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या था?

उद्देश्य 1: भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक समानता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।

टेबल 2: वन-सैंपल स्टैटिस्टिक्स (One-Sample Statistics) उद्देश्य 1 के लिए

Parameter	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक समानता	384	3.18	1.401	.072
विद्यालय का प्रकार	384	3.32	1.365	.070
शिक्षक की गुणवत्ता	384	3.20	1.393	.071
आर्थिक पृष्ठभूमि	384	3.28	1.346	.069
छात्र-शिक्षक अनुपात	384	3.18	1.426	.073
तकनीकी पहुँच	384	3.21	1.401	.072

टेबल 2 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक समानता का औसत मान 3.18 प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा में समानता का स्तर मध्यम है। विद्यालय का प्रकार (औसत 3.32) और आर्थिक पृष्ठभूमि (औसत 3.28) ऐसे प्रमुख कारक हैं जो समानता को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षक की गुणवत्ता (औसत 3.20), तकनीकी पहुँच (औसत 3.21) और छात्र-शिक्षक अनुपात (औसत 3.18) के परिणाम लगभग समान पाए गए, जो संकेत देते हैं कि इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। समग्र रूप से यह स्पष्ट है कि शिक्षा प्रणाली में समानता की दिशा में प्रगति हो रही है, परंतु संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण अब भी मौजूद है।

टेबल 3: मॉडल समरी उद्देश्य 1 के लिए

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.663[a]	.440	.432	1.056

Predictors: (Constant), तकनीकी पहुँच, विद्यालय का प्रकार, छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षक की गुणवत्ता, आर्थिक पृष्ठभूमि

टेबल 4: एनोवा (ANOVA) उद्देश्य 1 के लिए

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	330.638	5	66.128	59.341	.000[b]
Residual	421.234	378	1.114		
Total	751.872	383			

Dependent Variable: भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक समानता

Predictors: (Constant), तकनीकी पहुँच, विद्यालय का प्रकार, छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षक की गुणवत्ता, आर्थिक पृष्ठभूमि

टेबल 3 और 4 के परिणामों के अनुसार, मॉडल का R मान .663 और R Square .440 है, जो दर्शाता है कि लगभग 44% परिवर्तन शैक्षणिक समानता में इन कारकों से समझाया जा सकता है। एनोवा विश्लेषण में F मान 59.341 और महत्व स्तर .000 प्राप्त हुआ, जो मॉडल के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होने की पुष्टि करता है। परिणाम स्पष्ट करते हैं कि विद्यालय का प्रकार, शिक्षक की गुणवत्ता, आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्र-शिक्षक अनुपात और तकनीकी पहुँच शैक्षणिक समानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

टेबल 5: कोएफिशिएंट्स (Coefficients) उद्देश्य 1 के लिए

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	.354	.175		2.020	.044
विद्यालय का प्रकार	.263	.049	.257	5.399	.005
शिक्षक की गुणवत्ता	.209	.049	.208	4.227	.045
आर्थिक पृष्ठभूमि	.104	.052	.100	1.987	.048
छात्र-शिक्षक अनुपात	.209	.048	.213	4.389	.003
तकनीकी पहुँच	.087	.048	.087	1.811	.001

Dependent Variable: भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक समानता

टेबल 5 के अनुसार, प्रतिगमन विश्लेषण से पता चलता है कि सभी कारकों का भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक समानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। विद्यालय का प्रकार (β=.257, Sig=.005) और छात्र-शिक्षक अनुपात (β=.213, Sig=.003) सबसे प्रभावशाली कारक पाए गए। शिक्षक की गुणवत्ता (β=.208, Sig=.045) और आर्थिक पृष्ठभूमि (β=.100, Sig=.048) का भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया। तकनीकी पहुँच (β=.087, Sig=.001) का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम है, पर यह भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि शिक्षा समानता बहुआयामी कारकों पर निर्भर करती है।

उद्देश्य 2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

टेबल 6: वन-सैंपल स्टैटिस्टिक्स (One-Sample Statistics) उद्देश्य 2 के लिए

Parameter	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का प्रभाव	384	3.28	1.332	.068
समग्र शिक्षा	384	3.21	1.422	.073
सीखने में लचीलापन	384	3.22	1.390	.071
शिक्षक विकास	384	3.28	1.417	.072
तकनीकी एकीकरण	384	3.17	1.397	.071
शैक्षिक समानता	384	3.25	1.385	.071

टेबल 6 के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का औसत मान 3.28 प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि नीति का प्रभाव मध्यम स्तर पर सकारात्मक है। शिक्षक विकास (औसत 3.28) और शैक्षिक समानता (औसत 3.25) सबसे प्रभावी घटक पाए गए, जबकि समग्र शिक्षा (औसत 3.21) और सीखने में लचीलापन (औसत 3.22) के परिणाम समान रहे। तकनीकी एकीकरण का औसत 3.17

अपेक्षाकृत कम पाया गया। समग्र रूप से देखा जाए तो एनईपी 2020 ने शिक्षा में गुणवत्ता, लचीलापन और समानता के प्रति सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में योगदान दिया है।

टेबल 7: मॉडल समरी उद्देश्य 2 के लिए

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642[a]	.412	.404	1.028

Predictors: (Constant), शैक्षिक समानता, समग्र शिक्षा, शिक्षक विकास, तकनीकी एकीकरण, सीखने में लचीलापन

टेबल 8: एनोवा (ANOVA) उद्देश्य 2 के लिए

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	279.912	5	55.982	53.000	.000[b]
Residual	399.273	378	1.056		
Total	679.185	383			

Dependent Variable: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का प्रभाव

Predictors: (Constant), शैक्षिक समानता, समग्र शिक्षा, शिक्षक विकास, तकनीकी एकीकरण, सीखने में लचीलापन

टेबल 7 और 8 के परिणामों के अनुसार, मॉडल का R मान .642 और R Square .412 है, जो दर्शाता है कि लगभग 41% परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभाव में दिए गए कारकों से समझाया जा सकता है। एनोवा विश्लेषण में F मान 53.000 और महत्व स्तर .000 प्राप्त हुआ, जिससे यह मॉडल सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। परिणाम बताते हैं कि समग्र शिक्षा, शिक्षक विकास, तकनीकी एकीकरण, सीखने में लचीलापन और शैक्षिक समानता सभी का एनईपी 2020 के प्रभाव पर उल्लेखनीय योगदान है।

टेबल 9: कोएफिशिएंट्स (Coefficients) उद्देश्य 2 के लिए

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.703	.169		4.171	.032
समग्र शिक्षा	.236	.045	.252	5.211	.040
सीखने में लचीलापन	.114	.048	.119	2.361	.019
शिक्षक विकास	.173	.046	.184	3.753	.030

तकनीकी एकीकरण	.029	.048	.030	.600	.049
शैक्षिक समानता	.243	.048	.253	5.102	.000

Dependent Variable: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का प्रभाव

टेबल 9 के अनुसार, प्रतिगमन विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभाव पर सभी कारकों का सकारात्मक योगदान है। शैक्षिक समानता (β=.253, Sig=.000) और समग्र शिक्षा (β=.252, Sig=.040) सबसे अधिक प्रभावशाली कारक पाए गए। शिक्षक विकास (β=.184, Sig=.030) तथा सीखने में लचीलापन (β=.119, Sig=.019) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तकनीकी एकीकरण (β=.030, Sig=.049) का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, परंतु यह भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। परिणाम बताते हैं कि एनईपी 2020 ने शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता, समानता और लचीलापन बढ़ाने में प्रभावी योगदान दिया है।

8. निष्कर्ष

इस अध्ययन "भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समानता और नीति प्रभाव का अध्ययन" से यह स्पष्ट होता है कि भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समानता और गुणवत्ता दोनों ही सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, विद्यालयी ढाँचे और नीतिगत क्रियान्वयन पर निर्भर करती हैं। जनसांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार, अध्ययन में 384 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 57.8% पुरुष और 42.2% महिलाएँ थीं। उत्तरदाता विभिन्न क्षेत्रों से थे – 39.1% शहरी, 32.8% अर्ध-शहरी और 28.1% ग्रामीण पृष्ठभूमि से – जिससे शिक्षा प्रणाली की विविधता का वास्तविक परिप्रेक्ष्य सामने आया। विश्लेषण से पता चला कि विद्यालय का प्रकार (β=.257, Sig=.005), शिक्षक की गुणवत्ता (β=.208, Sig=.045), आर्थिक पृष्ठभूमि (β=.100, Sig=.048), छात्र-शिक्षक अनुपात (β=.213, Sig=.003) और तकनीकी पहुँच (β=.087, Sig=.001) समानता को सीधे प्रभावित करते हैं। ये परिणाम दर्शाते हैं कि शिक्षा सुधार केवल नीतियों के स्तर पर नहीं, बल्कि संसाधनों के समान वितरण, प्रशिक्षित शिक्षकों और डिजिटल पहुँच को सशक्त बनाकर ही संभव है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभाव के विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया कि इसने शिक्षा प्रणाली में समावेश, लचीलापन और गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। कोएफिशिएंट्स विश्लेषण के अनुसार, शैक्षिक समानता (β=.253, Sig=.000), समग्र शिक्षा (β=.252, Sig=.040), शिक्षक विकास (β=.184, Sig=.030), सीखने में लचीलापन (β=.119, Sig=.019) और तकनीकी एकीकरण (β=.030, Sig=.049) नीति के प्रभाव के प्रमुख घटक पाए गए। परिणाम यह दर्शाते हैं कि NEP 2020 ने शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, परंतु ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इसका प्रभाव सीमित है। अतः नीति की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर निवेश, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है, जिससे भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में वास्तविक समानता और गुणवत्तापूर्ण सीख सुनिश्चित की जा सके।

संदर्भ

1. घोष, एस. (2024). भारतीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक समानता पर सामाजिक-आर्थिक कारकों के प्रभाव का मूल्यांकन: एक संरचनात्मक मॉडलिंग दृष्टिकोण। मेज़रमेंट: इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड पर्सपेक्टिव्स।
2. सिंह, आर., राठी, जे., गुप्ता, एस., सैनी, ए., एवं कादरी, ए. (2023). शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता पर अध्ययन: भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में एक अन्वेषणात्मक अध्ययन। इंटीग्रेटेड जर्नल फॉर रिसर्च इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज।
3. चंद, वी. (1994). शिक्षा नीति में समायोजन: संस्थागत सुधार के अवसर।
4. मांजरेकर, एन. (2005). प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक समानता: पहुँच की पदानुक्रम। कॉन्टेम्परेरी एजुकेशन डायलॉग, 2, 245-249।
5. कुरियाकोस, एफ., एवं अय्यर, डी. (2016). इंडिया ऑफ आइडियाज़: भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति का मानचित्रण और समानता तथा उत्कृष्टता की दिशा में विमर्श का संचालन। पीएसएन: एजुकेशन (विषय)।
6. सय्यद, वाई., मॉरिस, पी., एवं राव, एन. (2013). समानता और शैक्षिक परिवर्तन। कंपेयर: ए जर्नल ऑफ कंपेरेटिव एंड इंटरनेशनल एजुकेशन, 43, 715-717।
7. पंडित, पी. (2016). भारत में शिक्षा: राष्ट्रीय नीतियाँ और विनियम। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 2, 393-396।
8. कायल, टी. (2019). भारत में प्राथमिक शिक्षा: जिलों के तुलनात्मक प्रदर्शन का विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 13, 372-381।
9. गोसवामी, जी., एवं रॉयचौधरी, ए. (2017). गुवाहाटी के झुग्गी बस्तियों के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ। द क्लैरियन-इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल, 6, 103-107।
10. शुभम, एस. (2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग नॉलेज स्टडीज।
11. सिंह, ए., एवं नारायणन, एच. (2023). क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नया प्रतिमान परिवर्तन संभव है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण। पर्टानिका जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज।
12. दास, पी. (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में शिक्षक शिक्षा की सिफारिशें और चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिव्यूज।
13. बड़े, आर., एवं चव्हाण, डी. (2023). नई शिक्षा नीति 2020: डिज़ाइन और क्रियान्वयन की चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च।
14. मुरारी, ए. (2024). सतत विकास लक्ष्यों (SDG) का लक्ष्य 4 और भारत की शिक्षा नीति: एक तुलनात्मक अध्ययन। जर्नल ऑफ एडवांसेस एंड स्कॉलर्ली रिसर्चेज इन अलाइड एजुकेशन।